1,540 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है देश में मौजूदा समय में। 1947 (आजादी के समय) यह आंकड़ा 5,000 घन मीटर था। ध्यान रहे भारत में प्रति वर्ष 400 करोड़ घन मीटर पानी वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है।

भारत और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंधों की नई शुरुआत

पीएम की यात्रा के दौरान किए गए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विगत में पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों की वजह से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने से परहेज करने वाले सऊदी अरब ने अपनी स्पष्ट राय बना ली है। सऊदी अरब ने भारत को न सिर्फ एक मजबूत रणनीतिक साझीदार के तौर पर चिन्हित किया है बल्कि उसे भविष्य में रक्षा उपकरणों के आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी देख रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच हुए 12 समझौतों में से तीन सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया सबसे अहम समझौता रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन से संबंधित है। जबकि दूसरा अहम समझौता सुरक्षा सहयोग से जुड़ा है। तीसरा समझौता दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच किया गया है जो इनके बीच हथियारों की खरीद-बिक्री, हथियारों के विकास व शोध के काम से जुड़े सहयोग को स्थापित करेंगे। जानकारों की मानें तो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ वर्ष 1982 का सुरक्षा सहयोग समझौता भी इतना व्यापक नहीं है। खासतौर पर रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन को लेकर पाकिस्तान के मीडिया व राजनीति में काफी हड़कंप मचा हुआ है। सऊदी अरब ने इसके पहले सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ ऐसा समझौता किया है। भारत यहां के पेट्रोलियम रिटेल में भी उसकी हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा भारत के पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार से भी सऊदी अरब का सीधा हित जुड़ा होगा। इसके लिए भी दोनों देशों के बीच मंगलवार को एक समझौता किया गया है।

▸ पाक से ज्यादा भरोसेमंद रक्षा सहयोगी के तौर पर होगी भारत की पहचान

रियाद में रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पीएम मोदी। प्रेट्र

चौथा देश है, जबकि आगे जापान, कोरिया, अमेरिका और रूस के साथ ऐसा ही समझौता करने की घोषणा की गई है। इसकी अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि परिषद की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान करेंगे। इसमें दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री सदस्य होंगे। इसके तहत कई उपसमितियां काम करेंगी जो समूचे रणनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सलाह देने का काम करेगी।

विदेश मंत्रालय के उच्चस्तरीय अधिकारियों के मुताबिक, सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में आयाम पूरी तरह बदलने लगे हैं। पहले दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ कच्चे तेल की खरीद-बिक्री तक सीमित थे जिसमें भारत की स्थिति कमोबेश एक याचक जैसी होती थी। लेकिन हालात बदलने लगे हैं और अगले चार-पांच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के परस्पर हित एक-दूसरे से जुड़े होंगे। सऊदी अरब की कंपनी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हिस्सेदार होगी और

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त दत्ता पडसलगीकर बने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त व महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दत्ता पडसलगीकर को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी-एनएसए) नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल के साथ आइबी में काम कर चुके हैं।

1982 बैच के आइपीएस अधिकारी पडसलगीकर ने 26 वर्षों तक खुफिया विभाग में सेवा दी। उन्हें वर्ष 2016 में मुंबई का पुलिस आयुक्त बनाया गया। वह 2018 में महाराष्ट्र के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए। महाराष्ट्र पुलिस के उनके सहयोगी 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की जांच में पडसलगीकर की भूमिका की सराहना करते हैं। पडसलगीकर ने आतंकियों के बीच हुई बातचीत का वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी अमेरिका से हासिल कर लिया था। जिंदा पकड़े गए पाक आतंकी अजमल कसाब के मामले में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनके साथी बताते हैं, 'मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद जब पडसलगीकर को सरकारी आवास आवंटित किया जाना था, वह वर्ली में आइपीएस अफसरों के भोजनालय में रहते थे। वह हर सुबह बिना सुरक्षा के पास की बेकरी में जाते थे।' गणेश उत्सव जैसे अवसरों पर अपने ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी के घर उनसे मिलने जाते थे।

ऐतिहासिक दिन से पहले मां का आशीर्वाद

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को देश के दो नये केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। इस ऐतिहासिक दिन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गांधीनगर स्थित अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री गुरुवार (आज) को देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। एएनआइ

मोदी ने कर्मचारियों से कहा, दूसरों के लिए आदर्श बने पीएमओ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पूरे सरकारी तंत्र के लिए आदर्श की तरह काम करे और अन्य मंत्रालयों को रास्ता दिखाने के लिए प्रेरणा एवं नेतृत्व प्रदान करे।

अपने आवास पर आयोजित 'दिवाली मिलन' कार्यक्रम के दौरान पीएमओ में कार्यरत कर्मियों को संबोधित करते हुए मोदी ने ये बातें कही। मोदी ने कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, सरकार की ओर से किए गए परिवर्तनकारी कार्य उनके अथक प्रयास और नियमित कोशिश से संभव हुआ है। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पीएम ने कर्मियों से गत वर्ष किए गए काम का आकलन करने और आने वाले साल के लिए ऊंचे लक्ष्य तय करने को कहा। उन्होंने कर्मचारियों से अपनी नैतिकता एवं प्राथमिकता के जरिये सरकार के अन्य हिस्सों के लिए प्रेरणा बनने का आह्वान किया। उन्होंने 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे किए जाने वाले लक्ष्यों को रेखांकित किया।

कर्नाटक सरकार पाठ्यक्रम से हटाएगी टीपू सुल्तान के चैप्टर

बेंगलुरु, एजेंसियां : कर्नाटक की भाजपा सरकार स्कूली इतिहास की किताबों से 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से संबंधित चैप्टर हटाएगी। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा, 'टीपू सुल्तान पर चैप्टर पाठ्यपुस्तकों में नहीं होने चाहिए, हम उन्हें जारी नहीं रहने देंगे। हम पहले ही 10 नवंबर को टीपू जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर नहीं मनाने का फैसला कर चुके हैं। क्योंकि वह विवादित शासक था और वह जबरन धर्मांतरण, मंदिरों के विध्वंस व हिंदुओं के उत्पीड़न में लिप्त था। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि टीपू सुल्तान स्वाधीनता सेनानी था।'

इससे पहले 28 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसायटी के प्रबंध निदेशक को भाजपा विधायक ए. रंजन के प्रस्ताव पर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। रंजन ने इतिहास की सभी पाठ्यपुस्तकों से टीपू सुल्तान का संदर्भ हटाने का प्रस्ताव किया था। सुरेश कुमार को लिखे पत्र में रंजन का कहना था कि पाठ्यपुस्तकों में टीपू को स्वाधीनता सेनानी के तौर पर दर्शाया गया है और इतिहास को गलत तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा जाना चाहिए। उनका कहना था, 'टीपू कोडागू, मेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में अपने राज्य का विस्तार करने आया था। वह यहां सिर्फ लोगों का धर्मांतरण कराने और अपने राज्य को बढ़ाने आया था। उसके मन में कन्नड़ भाषा के लिए कोई सम्मान नहीं था क्योंकि उसकी प्रशासनिक भाषा फारसी थी। उसने कई स्थानों के नाम भी बदले थे, मसलन मदिकेरी का जाफराबाद और मेंगलुरु का जलालाबाद। उसने कई मंदिरों और ईसाई चर्चों को भी लूटा था। कोडगु में उसने 30 हजार कोडावा लोगों का धर्मांतरण कराया था।'

▸ कांग्रेस ने सरकार के कदम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

टीपू सुल्तान के वंशज मुहम्मद शाहिद आलम ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए पूर्व शासक को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भाजपा को धर्मांध बताते हुए कहा, 'पाठ्यपुस्तकों से टीपू के चैप्टर हटाना इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने जैसा है। टीपू ने ब्रिटिश से लड़ाई की थी, यह सच है या झूठ? इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए। हमें बच्चों को इतिहास पढ़ाना होगा और उससे सीखना होगा।'

विदेश अदालत में ईडी की अर्जी खारिज न्यायिक हिरासत में भेजे गए चिदंबरम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दिन की रिमांड लेने के लिए अर्जी दायर की, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने चिदंबरम की खराब तबीयत को देखते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चिदंबरम को सुरक्षा के बीच अलग बैरक में रखा जाएगा। उन्हें घर का खाना और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

आइएनएक्स मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। कई दिन की रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीं दो सप्ताह पहले ईडी ने याचिका दायर कर चिदंबरम को हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को

▸ एक दिन के लिए रिमांड पर लेना चाहता था प्रवर्तन निदेशालय

कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बुधवार को नई दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के समक्ष पेश हुए। प्रेट्र

दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं न्यायिक हिरासत में जाने के बाद चिदंबरम ने अदालत के बाहर कटाक्ष किया। चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर में यूरोपीय संघ के सांसदों के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें संसद में आमंत्रित किया जा सकता है और सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं। चिदंबरम ने कहा कि कौन जानता है कि ऐसा हो भी सकता है?

डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ नया समन

जासं, नई दिल्ली : ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की पत्नी और मां के खिलाफ नया समन जारी किया गया है। हालांकि, दूसरी तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ को बताया कि अब तक उन्हें कोई समन नहीं मिला है। इस पर पीठ ने सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। डीके शिवकुमार फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनकी पत्नी ऊषा और मां गौवरम्मा की तरफ से दायर अलग-अलग याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील अमित महाजन ने पीठ को बताया कि जांच एजेंसी ने नया समन जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दयन कृष्णन ने दलील दी थी कि ईडी जब भी नया समन जारी करेगा उसे सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करना होगा। इसके तहत 15 साल से कम की किशोरी और 65 साल से अधिक उम्र की महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता। गौरम्मा 85 वर्ष की हैं और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहता है, तो वह उनके घर जा सकता है।

पानी नहीं बचाया तो केप टाउन बन जाएंगे चेन्नई व बेंगलुरु : शेखावत

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में गहराते जल संकट पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग पानी नहीं बचाने को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो देश की बहुत बड़ी आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित होगी और चेन्नई और बेंगलुरु केप टाउन बन जाएंगे।

बता दें कि वर्ष 2017-18 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन शहर में पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद वहां 'जीरो डे' का विचार आया। 'जीरो डे' का अर्थ उस दिन से है जब शहर के सभी नलों को बंद कर दिया जाता था। यहां 13वें विश्व एक्वा कांग्रेस में शेखावत ने कहा कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता आजादी के समय 5,000 घन मीटर से घटकर 1,540 घन मीटर रह गई है। अगर इसी तरह की गिरावट जारी रही और आबादी बढ़ती रही तो चेन्नई, बेंगलुर, केपटाउन बन जाएंगे और देश की आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।

शेखावत ने कहा कि तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आबादी और खराब जल प्रबंधन के कारण बेंगलुरु में नलकूप सूखने, भूजल स्तर गिरने और झीलें जहरीली होने लगी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पास नल वाला पानी नहीं पहुंच रहा है और वे पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। देश के एक और महानगर, चेन्नई में स्थिति बेहतर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औसतन भारत में प्रति वर्ष 1,068 मिमी बारिश और 4,00 करोड़ घन मीटर पानी वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर भी देश में जल संकट है। इजराइल में प्रति वर्ष 100 मिमी बारिश होती है। उतने में ही वह अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हुए वह पानी का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति भारत में जिम्मेदारी की भावना का अभाव है।

▸ दक्षिण के दो राज्यों में जल संकट पर जलशक्ति मंत्री ने चेताया

▸ दो साल पहले बूंद-बूंद पानी को तरस गई थी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी

गजेंद्र सिंह शेखावत फाइल फोटो

अरुणाचल के जरिये अमेरिका का चीन पर निशाना

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले पर चुप्पी साधने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जो एशिया में बदलते महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। इस बार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता का जोरदार समर्थन करते हुए पड़ोसी देश चीन की तरफ इशारा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह संकेत तब आया है जब भारत में उसके राजदूत केन जस्टर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए हैं। जस्टर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आयोजित एक फेस्टिवल में न सिर्फ बतौर प्रमुख अतिथि शामिल हुए बल्कि उन्होंने अमेरिकी सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने की घोषणा भी की।

तवांग को लेकर चीन हमेशा से सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा है। विदेशी राजनयिकों को छोड़ दिया जाए तो वह भारत के आला अधिकारियों के वहां जाने को लेकर भी आपत्ति जताता रहा है। तवांग पर चीन आधिकारिक तौर पर दावा करता रहा है और दो वर्ष पहले तवांग का चीनी भाषा में नाम भी अलग रख चुका है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के अपने मायने निकाले जा रहे हैं।

▸ अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अहम बयान, भारत की संप्रभुता को पूरा समर्थन

▸ राजदूत केन जस्टर के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद आया बयान

▸ तवांग पर चीन आधिकारिक तौर पर दावा करता रहा है

सातवें तवांग महोत्सव के उद्घाटन पर भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को प्रतीक चिह्न भेंट करते अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। एएनआइ

जस्टर ने ट्विटर पर तवांग फेस्टिवल में मनाए गए उत्सव की कई फोटो ट्वीट किए हैं।

बुधवार देर शाम अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिणी एवं केंद्रीय एशियाई मामलों के विभाग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जस्टर के फोटो और सूचना को रिट्वीट किया और लिखा, 'अमेरिकी राजदूत की तवांग यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि अमेरिका भारत की अखंडता में पूरी तरह से सहयोग करता है और स्थानीय साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। अमेरिका अरुणाचल में स्वास्थ्य व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है।' अमेरिका का यह आधिकारिक बयान ऐसे समय आया है जब पैसिफिक फ्लीट कमांडर के एडमिरल जॉन सी एक्वीलिनो ने दिल्ली में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर तल्ख टिप्पणी की थी। एक्वीलिनो ने कहा था कि जिस तरह से चीन हिंद महासागर में हथियारों की तैनाती कर रहा है उसने कई देशों के लिए चुनौती पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना आर्थिक नहीं सैन्य ताकत का प्रसार है। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन की तरफ से बढ़ता खतरा भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक सहयोग की गति को तेज करेगा।

तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का हुआ तबादला

नई दिल्ली, प्रेट्र : तीन हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों और दो हाई कोर्टों के जजों का बुधवार को तबादला कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही को मद्रास हाई कोर्ट भेजा गया है। सितंबर में जस्टिस विजया ताहिलरमानी के इस्तीफे के बाद से जस्टिस विनीत कोठारी मद्रास हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करौल को जस्टिस साही के स्थान पर पटना हाई कोर्ट भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के जज अकिल कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप पदोन्नत करने की सिफारिश की थी क्योंकि सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने पर आपत्ति व्यक्त की थी।

पटना हाई कोर्ट के जज का भी तबादला : पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भेजा गया है। इसी तरह, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अमित रावल का केरल हाई कोर्ट में तबादला किया गया है।

मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राज कुंद्रा से नौ घंटे पूछताछ

मुंबई, प्रेट्र : इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा से पूछताछ की। वह सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय पहुंचे थे और उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी इस इस मामले में गिरफ्तार बिंद्रा की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवेलपर्स में निदेशक धीरज वाधवान से भी पूछताछ करने की तैयारी में है।

अफसरों ने बताया कि ईडी ने कुंद्रा को समन जारी कर पूछताछ के लिए चार नवंबर को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता बताकर पहले हाजिर होने की इजाजत मांगी थी। इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि कुंद्रा का रंजीत बिंद्रा व बास्टियन हॉस्पिटैलिटी के साथ लेनदेन का मिर्ची मामले से ताल्लुक है या नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच लेनदेन के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए थी, इसलिए कुंद्रा को समन भेजा गया। हालांकि, इससे पहले कुंद्रा कह चुके हैं कि उन्होंने कारोबार में कुछ भी गलत नहीं किया। एजेंसी पिछले साल कुंद्रा से बिटकॉइन घोटाले में भी पूछताछ कर चुकी है।

▸ अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा से पिछले साल भी ईडी ने की थी पूछताछ

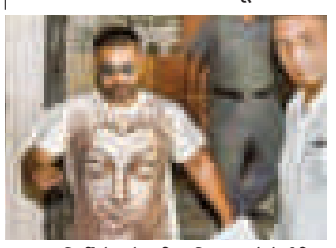

इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के मुंबई स्थित कार्यालय से पूछताछ के बाद बाहर आते बिजनेसमैन राज कुंद्रा। प्रेट्र

इकबाल मिर्ची गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी था और उसके अवैध काम को संभालता था। वर्ष 2013 में मिर्ची की लंदन में मौत हो गई थी। ईडी ने मिर्ची, उसके परिवार व अन्य के खिलाफ मुंबई में संपत्तियों की खरीदारी के मामले में मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। उसने मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज दर्जनों मुकदमे के आधार पर पीएमएलए की रिपोर्ट दाखिल की है। इस सिलसिले में ईडी ने पिछले कुछ महीनों में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की है।

सहिष्णुता भारतीय बहुसंख्यकों के डीएनए में : नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि सहिष्णुता एवं सामाजिक सद्भाव भारत के बहुसंख्यक समाज के डीएनए में है। भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सूत्रों के अनुसार, नकवी ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता विषय पर शीर्ष अमेरिकी राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अपने मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं एवं उनके सकारात्मक प्रभाव से भी अवगत कराया। इस मुलाकात के बाद नकवी ने ट्वीट किया, 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सशक्तीकरण तथा रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई।' सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक घंटे तक चली मुलाकात के दौरान नकवी ने अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों, खासकर लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। कहा, गत पांच वर्षों में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर 70 से 35 फीसद हो गई है।

घेराबंदी का प्रयास

बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार की घेराबंदी के लिए बैठक की पहल कर रही कांग्रेस, 5 से 15 नवंबर के बीच पार्टी देश भर में करेगी आंदोलन, संसद सत्र के दौरान सोनिया-मनमोहन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की करेंगे अगुआई

मंदी, रोजगार संकट पर होगी विपक्षी दलों की साझा बैठक

संजय मिश्र, नई दिल्ली

लगातार बिगड़ रही अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर चुकी कांग्रेस इस मसले पर साझा विपक्षी घेराबंदी के प्रयास में भी जुट गई है। पार्टी का मानना है कि आर्थिक मंदी ने रोजगार के संकट को गंभीर कर दिया है। ऐसे में सरकार को हालात की गंभीरता का अहसास कराने के लिए विपक्षी दलों की संयुक्त घेराबंदी जरूरी है। कांग्रेस इसी मकसद से विपक्षी दलों की साझा बैठक बुलाने की पहल कर रही है।

कांग्रेस के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति पर विपक्षी नेताओं से अनौपचारिक चर्चाएं चल रही है। अधिकतर विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सरकार की घेराबंदी की जरूरत को स्वीकार किया है। इसीलिए अगले चंद दिनों के भीतर ही आर्थिक मंदी की चुनौतियों पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। वामदलों के नेताओं ने बैठक के प्रस्ताव पर हामी भर दी है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर विपक्षी दलों के संयुक्त आंदोलन की फिलहाल कोई रूपरेखा नहीं बन रही। साझा बैठक का मकसद विपक्षी दलों की एकजुट ताकत से सरकार पर दबाव बढ़ाना है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुकी है और मंगलवार को इसकी रूपरेखा भी जारी कर दी गई। पार्टी का मानना है कि वैसे भी आर्थिक मंदी, रोजगार के संकट, कृषि संकट और किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाने की मुसीबत के अलावा मुक्त व्यापार से जुड़े आरसेप समझौते पर हस्ताक्षर की सरकार की तैयारी जैसे मसलों पर विपक्षी दलों की राय बहुत इतर होगी इसकी गुंजाइश नहीं है। वैसे विपक्षी दलों की एक बैठक आगामी संसद के शीत सत्र की संयुक्त रणनीति को लेकर भी होगी।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा की घोषणा की। इसके तहत पांच से 15 नवंबर के बीच प्रदेश की राजधानियों और हर जिले में लोगों को मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से रूबरू कराया जाएगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में संसद के शीत सत्र के दौरान दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में इस आंदोलन को परिणति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह इस प्रदर्शन की अगुआई करेंगे। राज्यों में विरोध आंदोलन में हीलाहवाली पर नजर रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है।

आर्थिक मंदी पर सरकार की घेराबंदी के आंदोलन को लेकर पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी ने दो नवंबर को सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और एआइसीसी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें मोदी सरकार की दूसरी पारी में कांग्रेस के इस पहले आंदोलन को कामयाब बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। आंदोलन को सियासी गरमी देने के लिए पार्टी 35 प्रमुख शहरों में प्रेस कांफ्रेंस के लिए प्रमुख नेताओं को भेजेगी, जो तथ्यों व आंकड़ों के साथ पर मोदी सरकार की विफलताएं गिनाएंगे।

'ध्यान' के लिए राहुल विदेश यात्रा पर, जल्द लौटेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'ध्यान' के लिए विदेश यात्रा पर हैं और उनके जल्द लौटने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में अटकलों का जवाब देते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वह अपनी नियमित 'ध्यान' यात्रा गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ध्यान सत्र के लिए संभवत: इंडोनेशिया में हैं। सुरजेवाला ने आगे बताया कि कांग्रेस ने आर्थिक मंदी, कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियां छिनने और आरसीईपी (रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) व्यापार समझौते के परिणाम जैसे मुद्दों पर पांच से 15 नवंबर तक देशव्यापी प्रदर्शनों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, 'पूरा कार्यक्रम उनके निर्देश और उनकी सलाह से ही तैयार किया गया है। उन्होंने उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और मुद्दों पर पार्टी का मार्गदर्शन किया है। जिस बैठक में कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया उसमें राहुल गांधी उपस्थित थे। राज्य और जिला स्तरीय इन कार्यक्रमों में न तो सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी हिस्सा लेने जा रहे हैं।'

कह के रहेंगे माधव जोशी